हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 138 देहरादून, शुक्रवार, 18 नवंबर, 2022 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

ग्राम प्रधानों को आपदा निधि से दी जाये 10-10 हजार रुपए की धनराशि : सतपाल महाराज 3

मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी : मुख्यमंत्री

पंचायती राज विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिये निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 17 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के ऐसे गांव जो भारत के प्रथम गांव हैं, उनके सुनियोजित विकास के लिए ''मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना'' शुरू की जायेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने माणा में आयोजित कार्यक्रम में सीमाओं पर स्थित गांवो को अंतिम गांव की बजाय प्रथम गांव कहा था। ये गांव देश के प्रथम गांव के साथ प्रहरी भी हैं। हमारी पहली प्राथमिकता इन गांवों का सुनियोजित विकास होना चाहिए।

गांवों में स्वच्छता के लिए 'मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र' योजना शुरू की जायेगी। जिसमें प्रत्येक गांव में एक पर्यावरण मित्र (स्वच्छक) की तैनाती की जायेगी। ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास के लिए 'मुख्यमंत्री चौपाल' शुरू की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं किसी गांव में जाकर चौपाल में प्रतिभाग करेंगे। ₹मुख्य सेवक चौपाल₹ में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी करेंगे।

सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे गांवों में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधार पर कुछ दिवस वहां के लिए विशेष महत्व के होते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गांवों में इन विशेष दिवसों को चिन्हित कर उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। ग्राम सभा का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इनमें उन गांवों के बाहर रहने वाले प्रवासी लोगों को प्रतिभाग करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जाए। उच्चाधिकारी भी इनमें प्रतिभाग करें। ग्राम पंचायतों का सुनियोजित विकास हो इसके लिए चौपाल लगाई जाए। चौपाल में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए एवं अधिकारी भी चौपालों में प्रतिभाग करें। इसके लिए ग्राम सभावार रोस्टर भी बनाया जाए। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इन चौपालों दिये जाने वाले सुझावों को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए गांवों के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि असली भारत गांवों में बसता है। राज्य के समग्र विकास के लिए गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास के लिए किसी गांव में एक कैबिनेट बैठक भी आयोजित की जाए, जिसमें गांवों के विकास से संबंधित प्रस्ताव हों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि 2025 में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनायेगा। तब तक गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में क्या प्रभावी प्रयास किये जा सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए हर गांवों के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए। अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का आम जन तक विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। सरकार की नई योजनाओं की आम जन को जानकारी हो इसके लिए गांवों में योजनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड लगाये जायें। सभी विभाग अपने स्तर से भी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास से संबंधित अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गांवों में लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। ग्राम प्रधानों को आपदा निधि के लिए दस-दस हजार रूपये की निधि प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। गांवों में चाल-खाल बनाने की दिशा में भी ध्यान दिया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव नितेश झा, निदेशक पंचायतीराज बंशीधर तिवारी, अपर सचिव ओंकार सिंह एवं पंचायतीराज विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

खटीमा में सीएम धामी का फूलों से हुआ स्वागत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

खटीमा, 17 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार राधा स्वामी सत्संग व्यास खटीमा पहुंचे। सीएम धामी के खटीमा पहुंचने पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत एसएसपी मंजूनाथ टीसी, सीडीओ विशाल मिश्रा, एसडीएम रविंद्र बिष्ट, जिलाध्यक्ष बीजेपी कमल जिंदल, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा,मंडी अध्यक्ष नन्दन सिंह खड़ायत सहित अमित पांडे, संतोष अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष किशोर जोशी, बलदेव सिंह, दीपक तिवारी आदि ने पुष्प देकर स्वागत किया। इसके साथ ही पुलिस विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने किया 48 वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैम्पियनशिप-2022 का शुभारंभ

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार, 17 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित पंतद्वीप मैदान पंहुचकर 48 वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैम्पियनशिप-2022 का द्वीप प्रज्जवलित कर शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने देश के 30 राज्यों से आये खिलाड़ियों के साथ सांकेतिक रुप से कबड्डी खेलते हुए खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में खिलाड़ियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलकर देश का नाम रोशन करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार निरंतर खेल प्रेमियों के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़ी है। उन्होने कहा कि जब भी वे खिलाडियों के बीच आते हैं तो उन्हे गौरव की अनुभूति होती है। कहा कि कबड्डी एक रोचक खेल है जिसे उन्होने बाल्यकाल में काफी खेला है। उन्होने कहा कि खिलाड़ियों के बीच आकर सकारात्मक उर्जा का संचार होता है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दूरस्थ गांवों में छुपी खेल प्रतिभा को मंच देने का कार्य कर रही है। कहा कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी जो अभाव या कमी के कारण अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते है उनके लिए प्रदेश सरकार समर्पण भाव से कार्य कर रही है। बच्चों में उर्जा का एक अलग ही स्तर होता है जिसे खेल में लगाकर खिलाड़ी नाम कमाने के साथ ही खेल को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल में हार जीत दो पहलू है जिसे खुले दिल से स्वीकर करना चाहिए। कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलकर प्रसिद्धि पाना सुखद होता है जिससे खिलाडी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।

कार्यक्रम विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिश्वरानंद, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविद्र पुरी महाराज, हरिद्वार महापौर अनिता शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, रुड़की भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, उत्तखण्ड कबड्डी एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष बृजभूषण विद्यार्थी समेत जिलाधिकारी डा0 विनय शंकर पांडेय , एसएसपी अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी मौजूद रहे।

जानिए सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के हैं ये 5 बड़े फायदे

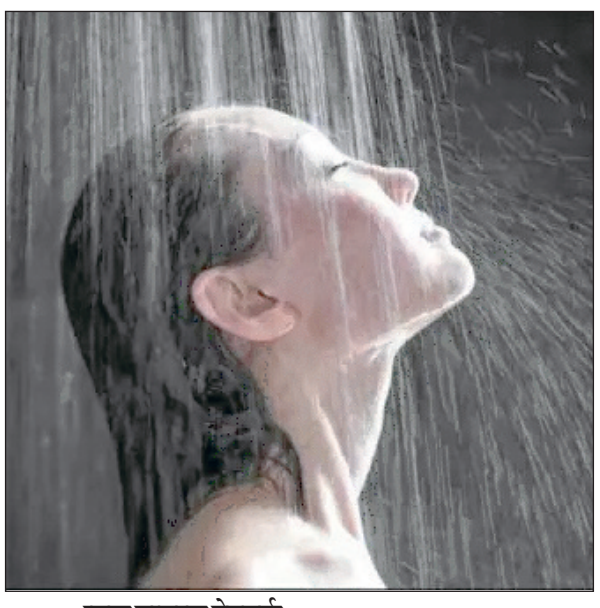

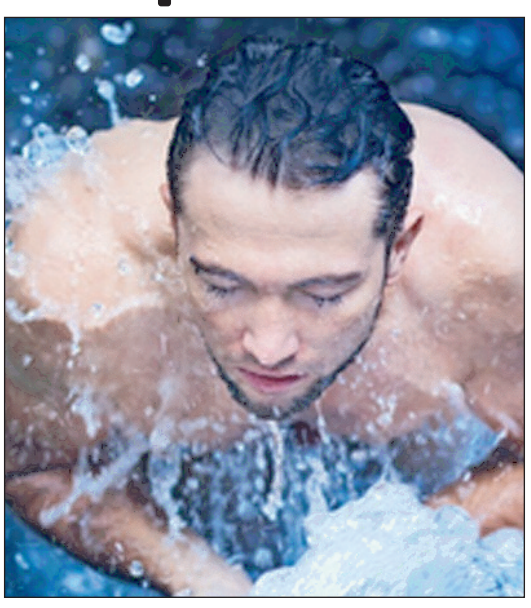

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोरट, 17 नवम्बर। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्नान करना आवश्यक है। यह मांसपेशियों में तनाव को दूर करने, रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और तनाव को कम करने के लिए फायदेमंद है।इसके अलावा, सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना गर्म पानी से ज्यादा मददगार होता है। ऐसा करने से आपको कई समस्याओं का सफल तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है।"

यह रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है

कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो यह ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार, आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे।

यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा हैक्या आपको पता है? सर्दियों में गर्म पानी से नहाने से त्वचा रूखी हो सकती है, जिससे त्वचा में जलन और रैशेज हो सकते हैं। यहां तक कि डैंड्रफ की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वे बंद होने से बच जाते हैं। यह त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, और गंदगी को अंदर जाने से रोक सकता है। इसलिए, प्राकृतिक तेल त्वचा से नहीं हटेंगे।"

ठंडा पानी इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता हैयदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं, तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में, सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है।

यह जल्दी मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता हैठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। यह कोल्ड कंप्रेशन जैसा है।"ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता हैठंडे पानी का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार, स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक आराम महसूस करेंगे।

"हम नई आए तो कौन सो तमाओ सकूल बंद हो जै", छुट्टी का पत्र वायरल

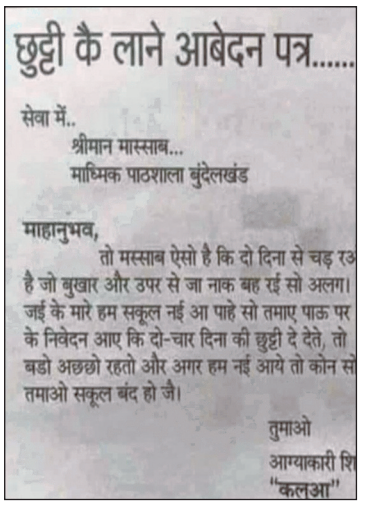

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 17 नवम्बर। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, जहां पर रोजाना ही कोई ना कोई नई चीज हमें देखने को मिल जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता है परंतु कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जिसे देखकर हर कोई सोच विचार में पड़ जाता है। इन दिनों ट्विटर पर कुछ ऐसी ही एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद हर कोई बहुत ज्यादा हंस रहा है।

बुदेलखंडी भाषा में लिखा गया एप्लिकेशन वायरल

जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जब भी छात्र को स्कूल से छुट्टियां लेनी होती है, तो उसके लिए पहले उन्हें छुट्टी का आवेदन पत्र स्कूल में जमा कराना पड़ता है। हम सभी लोगों ने भी बचपन में स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा होगा। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में। हालांकि, इस समय बुंदेलखंडी भाषा में लिखा गया एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

वैसे देखा जाए तो छुट्टी के लिए आवेदन को लिखना भी एक कौशल है। ऐसा ही एक स्कूली छात्र की छुट्टी का आवेदन पत्र इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे पढ़ने के बाद आप भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर इस मजेदार छुट्टी के एप्लीकेशन की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल हुआ ऐसा कि एक छात्र की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसने अपने स्कूल शिक्षक को छुट्टी के लिए आवेदन दिया है।

अपर मुख्य सचिव वित्त आनन्दवर्धन ने ऋणों के लक्ष्य को 75 प्रतिशत तक प्राप्त करने के निर्देश दिए

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 17 नवंबर। अपर मुख्य सचिव वित आनन्दवर्धन ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 83वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिसम्बर माह के अन्त तक सभी बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित किए जाने वाले ऋणों के लक्ष्य को 75 प्रतिशत तक प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम स्वनिधि के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का 30 नवम्बर तक निस्तारण का लक्ष्य बैंकों को दिया है।

अपर मुख्य सचिव ने केन्द्र एवं राज्य सरकार की एमएसएमई से सम्बन्धित ऋण योजनाओं में ओपरलेपिंग का परीक्षण कराकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए हैं। एसीएस ने सभी बैंकों को सरकार प्रयोजित ऋण योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा बैंक शाखाओं में लंबित ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण, स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने, विभिन्न सरकारी विभागों को निजी बैंकों को भी स्पेशल कॉम्पानेन्ट प्लान के तहत ऋण आवेदन भेजने, बैंक सखी, कॉमन सर्विस सेन्टर, राशन विक्रेताओं, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी बी. सी. (बैंक कॉरोस्पॉन्डेट) के कार्य प्रदान करने, बैंकों को राज्य के दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में नई शाखाए खोलकर राज्य में वितीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो में ऑवरलेपिंग की स्थिति प्रदर्शित हो रही है। बैंकों में एनपीए की वृद्धि को रोकने तथा बैंकिग को सस्टेनबल बनाने हेतु सभी सम्बन्धित विभागों से सहयोग एवं सार्थक प्रयास की अपेक्षा की गई है। बैठक में बैंकों से स्थानीय स्तर पर प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए एनपीए कम करने के प्रयास करने तथा तहसील से आर. सी. (रिकवरी सर्टिफिकेट) का मिलान करते हुए ऋण राशि की वसूली हेतु अमीनों का सहयोग प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में 103 गांव जो कि 05 कि0मी0 परिधि के अंतर्गत बैकिंग सेवाओं से आच्छादित नहीं है, की सूची जिला सहकारी बैंक को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि वे इन गांवों में शाखा खोलने की सम्भावनाओं का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार द्वारा पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई तथा पीएमजेजेबीवाई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक खाताधारकों को आच्छादित किए जाने के भी निर्देश मिले हैं।

इस दिशा में राज्य में 3159504 खाताधारकों को पीएमजेडीवाई, 2385330 खाताधारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 595833 खाताधारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 507324 खाताधारकों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है।

उत्तराखण्ड में 100 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम को प्रोत्साहित करने की दिशा में अल्मोड़ा तथा चमोली जिले आगे चल रहे हैं। अल्मोड़ा में 99 प्रतिशत तथा चमोली में 84 प्रतिशत बचत खाते डिजिटली आच्छादित हो चुके हैं। डिजिटाइजेशन के तहत रूपे कार्ड, आधार इनएबल्ड एवं इन्टरनेट कनेक्टीविटी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में अगले चरण में 1238 गांवों में फॉर जी टॉवर स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी जिलों की खसरा खतौनी भू-लेख पोर्टल पर दर्ज कर दी गयी है। अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल दो जिलों में भूमि का नक्शा बनाने कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष जिलों में कार्य प्रगति पर है।बैठक में सचिव कृषि बी वी आर सी पुरूषोतम, अपर सचिव सी रविशंकर, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई लता विश्वनाथन, एसएलबीसी संयोजक दिग्बिजय सिंह रावत तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारी व बैंक अधिकारी उपस्थित थे।

ग्राम प्रधानों को आपदा निधि से दी जाये 10-10 हजार रुपए की धनराशि : सतपाल महाराज

वार्षिक चरित्र प्रविष्टि पर मंतव्य अंकल हेतु शासनादेश को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए: महाराज

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 17 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायतों के सशक्तिकरण से संबंधित संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित कार्य, दायित्व, निधि, कार्मिक का पंचायतों में हस्तान्तरण हेतु उच्च स्तर पर निर्णय लेने और पंचायती राज विभाग एवं संबंधित विभागों के स्तर से अनेक महत्वपूर्ण विषयों और सुझावों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाया।

पंचायत मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ग्राम प्रधानों को आपदा निधि (त्वरित सहायता) के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि आपदा निधि से दिए जाने का भी सुझाव दिया जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति व्यक्ति की है। उन्होने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के शासनादेश 16 फरवरी 2005 के क्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा मुख्य विकास अधिकारी तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा खंड विकास अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि पर मंतव्य अंकन को लागू किया जाना अति आवश्यक है इसलिए शासनादेश का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए।

उन्होंने भारत सरकार के 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-ग में संशोधन के बाबत अध्यक्ष जिला पंचायत एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में राज्य विधान मंडल को ग्राम प्रधान नगर निगम की भांति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के विकल्प के संबंध में उच्च स्तर पर निर्णय लेते हुए इसे विधानमंडल दल से पास करवाने की भी बात कही।

महाराज ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों के मानदेय के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं के निराकरण के साथ साथ जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों को पंचायतों में हस्तान्तरण से पूर्व ग्राम प्रधान, पेयजल विभाग के कार्मिक एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की संयुक्त टीम के सत्यापन के उपरांत परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण की कार्यवाही पर विचार किए जाने का भी अनुरोध किया।पंचायत मंत्री ने पंचायत घरों के निर्माण हेतु 20 लाख के बजट का प्रावधान किए जाने, त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को अनुमन्य मानदेय राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत विकास कार्यों से ना होकर अधिष्ठान मद में अलग से बजट का प्रावधान किए जाने को भी कहा। पंचायत भवन एवं सरकारी भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायत की भूमि के उपयोग का भी उनके द्वारा उनके मुख्यमंत्री को सुझाव दिया गया।

अचानक बीच सड़क सीएम धामी ने रुकवाया काफिला, ये थी वजह

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 18 नवम्बर , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फ्लीट वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान से सचिवालय आ रही थी, इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओएनजीसी चौक के समीप स्कूटी पर संवार दो युवकों को स्कूटी से गिरते देखा। मुख्यमंत्री ने काफिला रूकवाकर दोनों युवकों हालचाल जाना, युवकों को मामूली चोट आई थी। मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनान पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि युवकों को शीघ्र आवश्यक उपचार उपलब्ध जाए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि दो पहिया वाहनों में यात्रा करते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें।

ट्रेन में गंदे तरीके से बनती है चाय चुस्की लेने से पहले पढ़ लें

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 17 नवंबर। भारत की 90 फीसदी जनता चाय की शौकीन है। इन्हें सुबह से लेकर रात तक हर समय चाय की तड़प लगती है। अब घर पर तो ये अपने हाथ की साफ सुथरी और बढ़िया क्वालिटी की चाय पी लेते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये कहीं बाहर होते हैं। बाहर बहुत सी जगह चाय बनाने में कोई खास साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। कई बार तो इनका चाय बनाने का तरीका इतना खराब होता है कि इसे देखकर आप हमेशा के लिए चाय पीना ही छोड़ दें।

ट्रेन में सफर करते समय भी कई लोग चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन हम आपको ट्रेन में चाय की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो आप देख कर ट्रेन में चाय पीना छोड़ देंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेन में गंदे तरीके से चाय बनाने का वीडियो फोटो बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो और तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे चाय विक्रेता ट्रेन के अंदर चाय बनाने के लिए पानी गरम करने की गंदी रॉड का इस्तेमाल कर रहा है।

चाय बनाने का यह गंदा तरीका ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने अपने मोबाइल में रिकार्ड कर लिया। उसने इस चाय विक्रेता को लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। चाय विक्रेता एक बर्तन में पानी गरम करने की एक रॉड डालकर चाय बनाता है। यह रॉड भी दिखने में बहुत गंदी होती है। जरा सोचिए इस चाय को पीने के बाद कितने लोगों बीमार पड़ सकते हैं।

यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। अधिकतर लोग इसे देखकर भड़क गए। एक यूजर ने लिखा "यह देखने के बाद मैं कभी ट्रेन में चाय नहीं पीऊँगा।" फिर दूसरे ने कहा "ये सरासर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।"

एक अन्य कहने लगा "ट्रेन में एक बार मैंने खाना पार्सल करते हुए देखा था। तब से ट्रेन में खाना पीना छोड़ दिया।" न्यूज़ वायरस भी आपसे गुज़ारिश करता है कि सफर के दौरान इस तरह के खाद्य पदार्थों की क्वालिटी और बेचने वाले की गतिविधियां परख कर ही इस्तेमाल करें वर्ना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं।

जल एवं खाद्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार देहरादून में हुआ आयोजित

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 17 नवंबर। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पार्टनर्स इन प्रोस्पेरिटी संस्था द्वारा आयोजित जल एवं खाद्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधन करते हुए कहा कि जल संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लगातार कार्य कर रही है। मंत्री जोशी ने कहा कि इस गोष्टी के माध्यम से निश्चित रूप से जो सुझाव आए है, उनपर विचार कर उसमे कार्य किया जाएगा। जल स्रोत के सुख जाने के संकट पर चिंता व्यक्त की और सभी से जल के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए जल का सदुपयोग करने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज जल के संरक्षण और उसके समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में देशभर में कई कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्री जोशी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसानो की आय दुगनी करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। आज प्रदेश में एप्पल मिशन में 12 करोड़ और कीवी के लिए 18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा फोकस जैविक और प्राकृतिक की खेती पर कर रही है ताकि किसानों की आय दोगनी होने के साथ साथ लोगो को प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा राज्य सरकार का संकल्प है कि जब प्रदेश 25 वर्ष का होगा तो उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी हो इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

इस अवसर पर एससी आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा, संस्था के सीईओ नरेश चौधरी, डॉ दीपांकर शाह, पीसी गोरखा, प्रशांत राय, आर एस चटर्जी, शशांक शेखर, डॉ.पंडित सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

लो अब सफर भी हुआ महंगा, वाहनों के किराये में बढ़ोतरी करने की तैयारी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 17 नवम्बर। प्रदेश में वाहनों का किराया बढ़ोतरी की प्रक्रिया काफी मुश्किल है। पिछले दिनों कई साल के बाद जो किराया बढ़ोतरी हुई थी, उसके लिए आरटीओ देहरादून की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। प्रदेश में बस, ट्रक, टैक्सी, विक्रम, ऑटो का किराया अब हर साल बढ़ाने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है जो कि 25 नवंबर को होने वाली राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक में रखा जाएगा। बैठक में सालाना बढ़ोतरी की दर भी तय कर दी जाएगी। दरअसल, प्रदेश में वाहनों का किराया बढ़ोतरी की प्रक्रिया काफी मुश्किल है। पिछले दिनों कई साल के बाद जो किराया बढ़ोतरी हुई थी, उसके लिए आरटीओ देहरादून की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। इसने सभी हितधारकों से बातचीत करके किराए का

प्रस्ताव एसटीए को भेजा था।इस पर आपत्तियां आने के बाद किराया बढ़ोतरी टल गई थी। इसके कई माह बाद दोबारा समिति ने सभी आपत्तियों को दूर करते हुए रिपोर्ट एसटीए को भेजी थी, जिसके बाद एसटीए ने किराया बढ़ोतरी की थी। इस लंबी प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए ही परिवहन मुख्यालय ने सालाना स्वतः किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। 25 नवंबर को होने वाली एसटीए बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा।

प्रदेश में अभी तक आरटीए के अलग-अलग नियम हैं। इन नियमों से लोगों को परेशानी होती है। आरटीए गढ़वाल में टैक्सी का परमिट तो आसानी से मिल जाता है लेकिन विक्रम के परमिट के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। कुमाऊं में विक्रम का परमिट आसानी से मिल जाता है लेकिन टैक्सी के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसी प्रकार, अलग-अलग नियमों के उल्लंघन में गढ़वाल और कुमाऊं में अलग-अलग सजा के प्रावधान भी हैं। परिवहन मुख्यालय ने इनमें एकरूपता लाने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव भी एसटीए की बैठक में रखा जाएगा।

भू माफिया सावधान ! वक़्फ़ बोर्ड खरीदेगा बुलडोज़र : अध्यक्ष शादाब शम्स का धाकड़ फैसला

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 17 नवंबर। उत्तराखंड में लगभग 15 फीसद आबादी अल्पसंख्यक समाज की है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है ... ऐसे में मुस्लिम समाज उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम किरदार निभाता है। लगभग आधा दर्जन विधानसभा ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक भाजपा और कांग्रेस के लिए जीत हार तय करते हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड में 22 साल बाद भी दोनों ही बड़ी पार्टियों में कोई बड़ा नेता नहीं बन पाया है। कांग्रेस में इक्का-दुक्का मुस्लिम चेहरों को छोड़ दे तो भाजपा में भी कोई साफ़ सुथरा और प्रभावशाली मुस्लिम फेस आज तक प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना पाया है जिसका प्रभाव सीएम ऑफिस में नज़र आता हो।

ऐसे में अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी और उनके मुद्दों की बात क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गुज़रे लगभग 6 सालों में उत्तराखंड को भाजपा सरकार के द्वारा शासित किया जा रहा है। यहां बीते 6 सालों में तीन मुख्यमंत्रियों ने सत्ता चलाई है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज की तरफ किसी ने तवज़्ज़ो ही नहीं दी है । यही वजह है कि उत्तराखंड में माइनॉरिटी से जुड़ी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के बजट की कोई कमी है या योजनाओं में कहीं कोई खामी है। लेकिन कमी है उन नेताओं की जो सरकार की योजनाओं और बजट को ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के भले में लगा सके।

अगर आज के हालात की बात की जाए तो उत्तराखंड में सबसे मालदार मुस्लिम इदारा है उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड ..... जिसकी अरबों रुपये की बेशकीमती सम्पत्तियाँ पूरे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और भू माफियाओं के चंगुल में फसी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 22 साल बाद भी इन संपत्तियों में या तो अवैध कब्जे हैं या वह नेताओं के मोटी कमाई की लालच में फंसकर धन उगाही का जरिया बन चुके हैं। अकेले देहरादून , मसूरी , हल्द्वानी , नैनीताल जैसे बड़े शहरों की बात करें तो यहां पर करोड़ों की वक़्फ़ संपत्तियां अवैध कब्जे में फंसी पड़ी है। लेकिन अब तक इस महकमे का जिम्मा संभालने वाले आंखें बंद

किए इस खेल को अपने नफे नुकसान के मुताबिक जारी रखे हुए हैं। एक तरफ जहां धामी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही कर रही है तो वहीं अल्पसंख्यक समाज के उन विभागों की तरफ अभी तक तवज्जो नहीं दी गई है जो भ्रष्टाचार की गर्त में डूबे हुए हैं। फिलहाल अब तेज़तर्रार भाजपा नेता शादाब शम्स को वक़्फ़ बोर्ड की बदहाली को सुधारने की अहम ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है जो बहुत बड़ी चुनौती नज़र आती है।

देहरादून के अल्पसंख्यक भवन में बैठने वाले विभागीय अधिकारी और सरकार के द्वारा बिठाए गए जिम्मेदार लोग भी काजल की कोठरी में इत्मीनान से बैठे हैं और समाज अपने हक और हुकूक के लिए धामी सरकार की तरफ ताक रहा है। मुस्लिम समाज के बड़े दानिश्वरों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बेहतरीन सरकार चला रहे हैं और उनकी नजर विकास पर दिखती है... ऐसे में अगर वह अल्पसंख्यक समाज की तरक्की की तरफ गंभीरता से प्रयास करें तो बदहाली की इस तस्वीर को बदला जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पार्टी में जो भी अल्पसंख्यक चेहरा है वह निजी स्वार्थ और लालच में समाज का भला करने की सोचता ही नहीं है। यही वजह है कि करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियां होने के बावजूद आज वक्त बोर्ड भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है ना उसका सर्वे कराया जाता है और ना ही उसकी आमदनी का कोई हिसाब किताब रखा जाता है क्योंकि इसका मोटा हिस्सा नेताओं को भेंट चढ़ाई जाती है।

बोर्ड के हालात बुरे मिले हैं लेकिन अब सुधारने की बारी - शादाब शम्स , चेयरमैन

इन चुनौतियों के बीच अल्पसंख्यक भवन के बोर्ड दफ्तर में बड़े इत्मीनान और हौसले के साथ नई नई योजनाओं को गिनाते हुए चेयरमैन शादाब शम्स कहते हैं कि पहली बार वो बुलडोज़र खरीदने जा रहे हैं और वो उन भू माफियाओं की आलीशान इमारत पर गरजेगा जो वक़्फ़ जायदादों पर अवैध बनायीं गयी है। इतना ही नहीं मोदी - धामी के सबका साथ सबका विकास के विजन को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ अरबों की खुर्द बुर्द , लापता और कब्ज़े में फसी जायदादों को पाक साफ़ करेंगे बल्कि बोर्ड की आमदनी बढ़ाते हुए पारदर्शी सर्वे भी जल्द कराया जायेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए निज़ाम में हालात सुधरेंगे और काजल की कोठरी में उम्मीद की रौशनी नज़र आएगी।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा MOSPI के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 17 नवंबर। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वधान में अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय संबंधी डाटा एकत्रीकरण हेतु उत्तर भारतीय राज्यों का दो दिवसीय क्षेत्रवार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होटल जे०एस०आर कॉन्टिनेटल, देहरादून में किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 राज्य जम्मू कशमीर, हिमांचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली उत्तराखण्ड, बिहार, लद्दाख के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इन राज्यों के साथ-साथ सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित थे। उत्तराखण्ड राज्य से अर्थ एवं संख्या, निदेशालय के अधिकारियों के साथ-साथ वन, मत्स्य, राज्य योजना आयोग तथा पर्यावरण निदेशालय के अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार से श्री राकेश कुमार मौर्य के ERT System of Environmental-Economic Accounting-Ecosystem Accounting को तैयार किये जाने की रूपरेखा एवं विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में भी पर्यावरणीय लेखांकन तैयार किया जायेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जीतेन्द्र सोनकर, अपर सचिव नियोजन द्वारा की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि राज्य के विकास एवं नीति निर्माण के लिए पर्यावरणीय लेखांकन महत्वपूर्ण होगा साथ ही जिसका प्रयोग नीति निर्माण में किया जायेगा। निदेशक अर्थ एवं संख्या द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में पर्यावरण को अर्थव्यवस्था से जोड़ना अति आवश्यक है क्योंकि बिना पर्यावरण संरक्षण के अर्थव्यवस्था का विकास की परिकल्पना करना असम्भव है। राज्य में 71 प्रतिशत के अधिक वन क्षेत्र है।

इस अवसर पर मेजर योगेन्द्र यादव, अपर सचिव नियोजन श्री एस०पी०सुबुद्धि, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड सुशील कुमार, निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, डॉ० मनोज कुमार पंत, चित्रा कार्यक्रम की नोडल अधिकारी, निर्मल कुमार शाह, सतेन्द्र कुमार अग्रवाला, शालू भटनागर, अशोक कुमार, ब्रिजेश कुमार आदि उपस्थित थे।

महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी में हुआ व्यापारिक समझौता

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

महाराष्ट्र/देहरादून, 18 नवम्बर। महाराष्ट्र के राजभवन में उत्तराखंड व महाराष्ट्र के बीच व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की उपस्थिति में महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कोमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (MACCIA) व सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखण्ड (SMAU) के मध्य समझौता हस्ताक्षर किया गया।इस अवसर पर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन ललित गांधी, सिडकुल मनुफैक्चर्स एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ0 हरिंद्र कुमार गर्ग, महाराष्ट्र चेंबर ट्रस्ट बोर्ड अध्यक्ष आशीष पेडणेकर, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स करुणाकर शेट्टी, सचिव सिडकुल मनुफैक्चर्स एसोसिएसन राज अरोरा, शैलेश अजमेरा, चेंबर महिला समिति अध्यक्ष संगीता पाटिल, टॉम थॉमस, खुबिलाल राठोड, अविक्षित रमण आदि लोग मौजूद रहे।।

बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर फूटा मंत्री चंदन राम दास का गुस्सा, सख्त कार्यवाही के आदेश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 17 नवंबर। समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास ने राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में 19% धनराशि एससीएसपी के लिए तथा 3% धनराशि टीएसपी के लिए निर्धारण के संबंध में समीक्षा बैठक की।मंत्री ने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा करते हुए जारी स्वीकृत राशि के सापेक्ष कम व्यय पर नाराजगी जताते हुए खर्च की सीमा बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने विभागीय बजट जारी करने में विलम्ब न करते हुए कहा कि जिस योजना मद में बजट जारी हुआ है उसे उसी मद में व्यय किया जाय। उन्होंने एससीएसपी तथा टीएसपी धनराशि के दुरपयोग होने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये।मंत्री ने कहा कि इस मद से हम गरीबों की सीधे तौर पर मदद कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जिला सेक्टर और केन्द्र सेक्टर मद की अलग से समीक्षा की जाय। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लानी होगी तथा आवश्यकतानुसार भवन, स्कूल, शौचालय, लाईब्रेरी, अस्पताल आदि बनाने होंगे।मंत्री ने कहा कि बजट व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल विभाग को भेजा जाय ताकि अगली किश्त जारी की जा सके। उन्होंने अधिकारियों द्वारा अधूरी सूचना लाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना पर विशेष जोर देना होगा।मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी तथा आगामी बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 1338.49 लाख रूपये रही जिसमें 938.95 लाख रूपये व्यय किये गये जोकि बजट के सापेक्ष 14.16% रहा। कृषि विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 464.84 लाख रूपये रही जिसमें 317.57 लाख रूपये व्यय किये गये जोकि बजट के सापेक्ष 28.05% रहा। पशुपालन विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 952.96 लाख रूपये रही जिसमें 582.70 लाख रूपये व्यय किये गये जोकि बजट के सापेक्ष 39.44% रहा। पशुपालन विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 149.87 लाख रूपये रही जिसमें 95.00 लाख रूपये व्यय किये गये जोकि बजट के सापेक्ष 16.45% रहा। वन विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 1093.75 लाख रूपये रही जिसमें 834.40 लाख रूपये व्यय किये गये जोकि बजट के सापेक्ष 43.06% रहा। वन विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 127.28 लाख रूपये रही जिसमें 19.96 लाख रूपये व्यय किये गये जोकि बजट के सापेक्ष 18.86% रहा। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 2103.14 लाख रूपये रही जिसमें 969.54 लाख रूपये व्यय किये गये जोकि बजट के सापेक्ष 32.32% रहा। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 1613.92 लाख रूपये रही जिसमें 1321.34 लाख रूपये व्यय किये गये जोकि बजट के सापेक्ष 33.55% रहा।

इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एल. फनई, सचिव अरविन्द ह्यांकी, निदेशक जनजाति संजय सिंह टोलिया तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय

सस्ती होंगी दवाइयां

दवाओं को आम जन के लिए सस्ता और सुलभ बनाने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने कई जीवनरक्षक दवाओं को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है. उपचार के खर्च में सबसे अधिक हिस्सा दवाओं का होता है. आम तौर पर बाजार में दवाओं की कीमत निर्माता कंपनियां निर्धारित करती हैं. उनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है. ऐसी शिकायतें अक्सर सामने आती हैं कि दवा कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए चिकित्सकों और अस्पतालों को रिश्वत भी देती हैं. ऐसे में दवाओं की कीमत स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाती हैं. सरकार ने जिन 384 दवाओं को आवश्यक दवा की श्रेणी में डाला है, उनमें कैंसर, दर्द निवारक, न्यूरो से संबंधित रोगों, डायबिटीज, टीबी और हृदय रोग की दवाएं शामिल हैं. हमारे देश में ये रोग तेजी से बढ़ भी रहे हैं तथा इनका इलाज भी महंगा होता है. इन रोगों से ग्रस्त लोगों को निश्चित ही राहत मिलेगी. उल्लेखनीय है कि जिन दवाओं को इस सूची में रखा जाता है, उनके दाम राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं. इसका मतलब यह है कि दवा कंपनियां, अस्पताल और फार्मेसी दुकानें उन्हें मनमानी कीमत पर नहीं बेच सकती हैं. नियमों के अनुसार सभी अस्पतालों को, चाहे वे निजी अस्पताल हों या सरकारी, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में उल्लिखित दवाओं की बड़ी खेप अपने पास रखनी होगी. यह प्रावधान इसलिए जरूरी है क्योंकि संभव है कि अस्पताल में इन दवाओं की उपलब्धता न हो और रोगी के लिए महंगे विकल्पों को खरीदना मजबूरी बन जाए. समय समय पर दाम, असर और उपलब्धता के आधार पर इस सूची में दवाओं को शामिल किया जाता है या हटाया जाता है. दवाओं का परीक्षण और निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर किया जाता है. सितंबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी थी कि सरकार राष्ट्रीय सूची की समीक्षा कर रही है. इस सूची को आखिरी बार 2015 में संशोधित किया गया था. उस समय इसमें 376 दवाएं थीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने तथा समाज के निर्धन और निम्न आय वर्ग को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मुहैया कराने को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है. दवाओं की सूची को अपडेट करने के साथ-साथ जन औषधि केंद्र भी खोले गये हैं. इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं बहुत कम दाम पर मिलती हैं. ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां दवाओं का समुचित स्टॉक रहे. ऐसी योजनाएं स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर बदल सकती हैं.

प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल एक साल और बढ़ा

नई दिल्ली, नवम्बर, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक साल और बढ़ गया है। उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। इसके साथ ही वह अब नवंबर 2023 तक ईडी के निदेशक के पद पर बने रहेंगे। यह तीसरी बार है, जब उन्हें लगातार सेवा विस्तार दिया गया है।

सरकार पिछले साल एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें यह अनुमति दी गई थी कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल दो साल की अनिवार्य अवधि के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

मिश्रा को बाद में एक साल विस्तार दिया गया था, जो कि दूसरी बार था। गुरुवार के आदेश में कहा गया, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में एक वर्ष की अवधि (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। 60 वर्षीय मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और 19 नवंबर, 2018 को उन्हें ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। ईडी निदेशक का निश्चित कार्यकाल दो साल होने की वजह से उनका कार्यकाल अगले हफ्ते खत्म हो रहा था।

ईडी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। यह एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2018 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के आपराधिक प्रावधानों को लागू करता है।

जी-4 देशों की चेतावनी : UNSC में सुधार का सही समय, जितनी ज्यादा देर होगी- उतना ज्यादा नुकसान होगा

संयुक्त राष्ट्र, नवम्बर, एजेंसी। जी-4 राष्ट्रों ने गुरुवार को चेतावनी दी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सुधारों को जितना लंबा रोका जाएगा, प्रतिनिधित्व में उतना ज्यादा घाटा होगा। इन राष्ट्रों ने कहा कि यूएनएसी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से निकाय मौजूदा संघर्षों को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम होगा। जी-4 देशों में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व का मुद्दा चालीस साल पहले 1979 को महासभा के एजेंडे में शामिल किया गया था। यह खेदजनक है कि इस मुद्दे पर चार दशकों के बाद भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद के पास यह अपने चार्टर उत्तरदायित्व के अनुरूप काम करने का सही समय है। स्थायी प्रतिनिधि कंबोज ने आगे कहा कि यूएनएससी की सदस्यता बढ़ाए बिना इसके लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकेगा। यही परिषद दुनिया भर में आज के संघर्षों के साथ-साथ तेजी से जटिल और आपस में जुड़ी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में सक्षम होगी।

आयकर विभाग ने कर्नाटक में मारे छापे, 1300 करोड़ रुपये के काले धन का पता लगाया

दिल्ली, 17 नवम्बर, एजेंसी। आयकर विभाग ने गुरुवार को कालेधन के खिलाफ एक अभियान चलाते हुए कर्नाटक में छापे के बाद 1300 करोड़ रुपये की बेहिसाब अघोषित आय का पता लगाया है। विभाग ने 20 अक्टूबर 2022 और दो नवंबर को कुछ ऐसे व्यक्तियों पर तलाशी अभियान चलाया, जिन्होंने विभिन्न रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ संयुक्त विकास समझौते (जेडीए) निष्पादित किए थे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, 20 अक्टूबर और दो नवंबर को बेंगलुरु, मुंबई और गोवा में फैले 50 से अधिक रियल एस्टेट डेवलपर्स के परिसरों में छापे मारे गए। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि अब तक तलाशी अभियान में 1300 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है। इसके अलावा, 24 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और सोने के आभूषण आदि अघोषित संपत्ति भी जब्त की गई है।

तलाशी अभियान के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य मिले और जब्त किए गए। आगे बयान में कहा कि यह भी पाया गया कि कुछ भूस्वामियों ने विभिन्न वर्षों के लिए अपने आईटीआर भी दाखिल नहीं किए, जहां उन्हें पूंजीगत लाभ आय अर्जित हुई थी।

आगे कहा कि बिक्री समझौतों, विकास समझौतों और अधिभोग प्रमाणपत्र (OCs) के संबंध में साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। इन साक्ष्यों से पता चला कि प्राधिकरणों से ओसी जारी होने के बाद भी भूस्वामियों ने विभिन्न विकासकर्ताओं को जेडीए के माध्यम से विकास के लिए दी गई भूमि के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ से अर्जित आय का खुलासा नहीं किया था।

जब कर चोरी की बात कारोबारियों के सामने रखी गई तो उन्होंने अपनी चूक स्वीकार की और अपने संबंधित मामलों में पाए गए पूंजीगत लाभ से आय का खुलासा करने और उस पर देय करों का भुगतान करने पर सहमत हुए। वहीं आगे की जांच चल रही है।

दैनिक
न्यूज वायरस
न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।
सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002
email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा

सभी महाविद्यालयों में नैक एक्रिडिएशन होगा अनिवार्य : डॉ0 धन सिंह रावत

शिक्षण संस्थानों को मार्च 2023 तक कराना होगा नैक मूल्यांकन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 17 नवंबर। सूबे के समस्त महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कराना होगा, इसके लिये सभी राजकीय एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को मार्च 2023 तक का समय दिया गया है। नैक एक्रिडिएशन न कराने वाले महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये महाविद्यालयों को कम से कम 180 दिन कक्षाएं संचालित करने को कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप महाविद्यालयों में ग्रीन कैम्पस, तम्बाकू मुक्त कैम्पस बनाने हेतु समितियों का गठन करने तथा एनसीसी, एनएसएस एवं रोवर रेंजर की इकाईयां स्थापित की जायेंगी। छात्र-छात्राओं की डिजीटल हेल्थ आईडी बनाने के साथ ही उनके ब्लड ग्रुप की भी जांच महाविद्यालय स्तर पर की जायेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में विभागीय बैठक में राजकीय एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने सभी अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को अनिवार्य रूप से नैक मूल्यांकन कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2023 तक नैक मूल्यांकन सुनिश्चित करायें। नैक मूल्यांकन न कराने वाले अशासकीय महाविद्यालयों की जहां मान्यता खत्म कर दी जायेगी वहीं राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

डॉ0 रावत ने बताया कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के सहयोग से माह दिसम्बर में विभिन्न जनपदों में पांच सेमीनार आयोजित किये जायेंगे जहां पर नैक मूल्यांकन के लिये आवश्यक सुविधाओं एवं संरचनाओं की जानकारी दी जायेगी ताकि नैक मूल्यांकन में महाविद्यालयों को सहूलियत हो सके। डॉ0 रावत ने उच्च शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार के लिये सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से 180 दिन कक्षाओं का संचालन करने, निश्चित समय सीमा के भीतर परीक्षाओं का आयोजन व परिणाम जारी करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।

बैठक में विभागीय मंत्री ने राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालों के प्राचार्यों को एंटी ड्रग्स सेल का गठन करने के साथ ही तम्बाकू मुक्त परिसर एवं ग्रीन कैम्पस बनाने को कहा, साथ ही उन्होंने महाविद्यालयों में एनएसएस, एनसीसी एवं रोवर्स रेंजर की इकाईयां स्थापित करने व शिक्षकों एवं कार्मिकों के साथ ही छात्र-छात्राओं की भी बायोमैट्रिक उपस्थिति लिये जाने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों से टीबी मुक्त उत्तराखंड अभियान से जुड़ कर एक-एक टीबी मरीज गोद लेने, छात्र-छात्राओं की डिजीटल हेल्थ आईडी बनाने, प्रत्येक छात्र-छात्राओं के ब्लड ग्रुप की पहचान करने व स्वैच्छिक रक्तदान के लिये पंजीकरण कराने को भी कहा। बैठक में निर्णय लिया कि सभी राजकीय महाविद्यालयों में 4-जी कनेक्टीविटी के लिये संबंधित प्राचार्य किसी भी नेटवर्क कंपनी से उपलब्धता के आधार पर कनेक्शन ले सकते हैं। जिसका भुगतान मासिक या वर्षिक आधार पर छात्र निधि से प्राप्त धनराशि से किया जा सकता है। विभागीय मंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के महाविद्यालय अपने आस-पास के एक-एक गांव को गोद लेकर साक्षरता, स्वच्छता एवं सामाजिक जन जागरूकता अभियान चलायेंगे जबकि मैदानी क्षेत्रों के महाविद्यालय अपने आस-पास के एक-एक राजकीय विद्यालय व बालवाटिका को गोद लेकर सहयोग करेंगे। डॉ0 रावत ने कहा कि सूबे के महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ अंतर महाविद्यालय संस्कृतिक, खेल, सामान्य ज्ञान व भाषण प्रतियोगिता सहित अंतर विश्वविद्यालय कुलगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, अपर सचिव प्रशांत आर्य, सलाहकार रूसा प्रो0 एम0एस0एम0 रावत, प्रो0 के0डी0 पुरोहित, निदेशक उच्च शिक्षा प्रो0 प्रवीन जोशी, संयुक्त निदेशक प्रो0 ए0 एस0 उनियाल के साथ ही सभी 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे जबकि राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

कैंट में भारत जोड़ों यात्रा में उमड़ी भीड़, जोश में दिखी कांग्रेस : सूर्यकांत धस्माना

धस्माना ने यात्रा शुरू होने से पहले राम मंदिर में की पूजा अर्चना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 17 नवंबर। कन्या कुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के साथ सद्भावना ब समर्थन व्यक्त करने व यात्रा के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वाहन पर शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के तहत देहरादून की कैंट विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना के नेतृत्व में विशाल भारत जोड़ो यात्रा निकाली गयी जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं व युवाओं ने भागीदारी निभाई। कैंट क्षेत्र के श्रीदेव सुमन नगर वार्ड के दीपलोक मित्रलोक स्थित राम मंदिर से यात्रा की शुरुआत से पहले सूर्यकांत धस्माना ने श्री राम मंदिर में राम दरबार में हाजरी लगा कर पूजा अर्चना कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की कामना की व आरती कर प्रसाद ग्रहण किया व तत्पश्चात यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो , भारत के हैं चार सिपाही हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई, वंदे मातरम, भारत माता की जय के अलावा अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो व वीआईपी का नाम बताओ तथा यूके ट्रिपल एस सी घोटाले का पूरा पर्दाफाश करो जैसे नारे लगाते हुए यात्रा श्रीदेवसुमन नगर से बल्लूपुर वार्ड में राजेंद्र नगर, महेंद्र विहार, गांधी नगर होते हुए चोर खाला, शांति विहार, गोविंदगढ़, यमुना कालौनी के कुम्हार मंडी होते हुए चकराता रोड में यमुना कालौनी गेट पर समाप्त हुई जहां एक सभा का आयोजन किया गया।

भारत से नफरत को भगा कर फिर से देश को प्रेम से जोड़ना होगा : धस्माना

सभा को संबोधित करते हुए सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज देश में सत्ता पर काबिज लोग ही देश में नफ़रतें फैलाने का काम कर देश को धर्म जाती भाषा व क्षेत्र के आधार पर बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में आम आदमी की समस्याओं के समाधान करने में असफल सत्तासीन अपनी असफलता को छुपाने के लिए व सत्ता में बने रहने के लिए देश में नफरतों की खेती कर रहे हैं और यह देश की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने ने कहा कि आज ऐसे नाजुक मौके पर राहुल गांधी ने एक बहुत साहसी कदम उठाया है जैसा 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दे कर अंग्रेज़ी हुकूमत को चुनौती दी और अब 2022 में राहुल गांधी ने नफरत भारत छोड़ो का नारा दे कर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लाखों लोग उनके साथ पैदल चल रहे हैं। वरिष्ठ नेता धस्माना ने कहा कि अपनी केंद्र की सरकार के पदचिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड की सरकार भी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी यूनिफार्म सिविल कोड तो कभी धर्मान्तरण बिल का राग अलाप रही है जबकि प्रदेश में यूके ट्रिपल एस सी भर्ती घोटाले, अंकिता भंडारी हत्याकांड, विधानसभा भर्ती घोटाला समेत तमाम जन मुद्दे सरकार के सामने मुसीबत बन के खड़े हैं जिनका कोई जवाब बीजेपी सरकार नहीं दे पा रही इसलिए वो भी केवल ध्रुवीकरण के बल पर अपनी खाल बचाने का प्रयास कर रही है।

सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि नकली बातों से न प्रदेश चलता है न देश इसलिए कांग्रेस नफरतों और बांटने की राजनीति को परास्त करने के लिए भारत जोड़ो का महा अभियान चला रही है जो निश्चित रूप में सफल होगा।महानगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कैंट के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी सभी लोग एकजुट हो कर श्री धस्माना के नेतृत्व में जनहित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस द्वारा देहरादून के लिए पर्यवेक्षक राजवीर सिंह चौहान, महामंत्री जगदीश धीमान, प्रदेश सचिव मंजू त्रिपाठी, नगर निगम की तीनों पार्षद सुमित्रा ध्यानी, कोमल वोहरा, संगीता गुप्ता, तीनों ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, विक्रांत राठी व जितेंद्र तनेजा, महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव पिया थापा, प्रदेश प्रवक्ता दीप वोहरा, अवधेश कथिरिया, अनुराग गुप्ता, सलीम अंसारी, मेहमूदन, राम कुमार थपलियाल, एसपी बहुगुणा, अनुज दत्त शर्मा, मेहताब, सुभान , इकराम , अनीता दास , मीनाक्षी बिष्ट समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।